29-02-2024

प्रधानमंत्री द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) का दौरा किया और लगभग 1800 करोड़ रुपये की तीन महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में एसएलवी एकीकरण सुविधा (पीआईएफ); महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई 'सेमी-क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा'; और वीएसएससी, तिरुवनंतपुरम में 'ट्राइसोनिक विंड टनल' शामिल हैं।
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा (पीआईएफ) पीएसएलवी प्रक्षेपण की आवृत्ति को प्रति वर्ष 6 से 15 तक बढ़ाने में मदद करेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा एसएसएलवी और निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए अन्य छोटे प्रक्षेपण व्हिकल्स के प्रक्षेपण को भी पूरा कर सकती है।
- आईपीआरसी महेंद्रगिरि में नई 'सेमी-क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा' सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और चरणों के विकास को सक्षम करेगी, जो वर्तमान लॉन्च व्हिकल्स की पेलोड क्षमता को बढ़ाएगी। यह सुविधा 200 टन तक के थ्रस्ट वाले इंजनों का परीक्षण करने के लिए तरल ऑक्सीजन और केरोसिन आपूर्ति प्रणालियों से सुसज्जित है।
- वायुमंडलीय उड़ान के दौरान रॉकेट और विमानों के वर्गीकरण के लिए एयरोडायनेमिक टेस्टिंग के वास्ते विंड टनल्स आवश्यक हैं। वीएसएससी में जिस "ट्राइसोनिक विंड टनल" का उद्घाटन किया जा रहा है, वह एक जटिल तकनीकी प्रणाली है। यह हमारी भविष्य की प्रौद्योगिकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
- इसके आलावा प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की और नामित चार अंतरिक्ष यात्रियों को 'एस्ट्रोनॉट विंग्स' प्रदान किये। नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। गौरतलब है कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में

- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) में स्थित है जो मोचन रॉकेट प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार इसरो का प्रमुख केंद्र है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई | इसकी शुरुआत थम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर हुई थी लेकिन इसका पुनः नामाकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ॰ विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया है।
- यह केंद्र विभिन्न मिशनों के लिए उप-प्रणालियों की प्राप्ति से संबंधित डिजाइन, निर्माण, विश्लेषण, विकास और परीक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है।
- ये कार्यक्रम, योजना और मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्योग समन्वय, मानव संसाधन विकास और सुरक्षा गतिविधियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।
- वीएसएससी के प्रमुख कार्यक्रमों में ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट(P S L V), भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (GSLV) और रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट के साथ-साथ भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (GSLV) MK III, पुनरुपयोगी प्रमोचन रॉकेट, उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन, श्वसन नोदन और समानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

ऑटोमोटिव MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी कार्यक्रम

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में 'भविष्य का निर्माण - ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मोबिलिटी' कार्यक्रम में भाग लिया, और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) उद्यमियों को संबोधित किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एमएसएमई को समर्थन और उत्थान के लिए डिजाइन की गई दो प्रमुख पहलों की भी शुरुआत की। इन पहलों में टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म और टीवीएस मोबिलिटी-सीआईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं।
- ये पहल देश में एमएसएमई के विकास का समर्थन करने और उन्हें संचालन को औपचारिक बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के प्रधानमंत्री के

विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री के अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7 प्रतिशत का योगदान है और देश में इसका विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है|

- भारत में हर साल 45 लाख से अधिक कारें, 2 करोड़ दोपहिया वाहन, 10 लाख वाणिज्यिक वाहन और 8.5 लाख तिपहिया वाहन का उत्पादन होता है।
- प्रधानमंत्री ने मोटरवाहन और मोटरवाहन के पुर्जो के लिए 26,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना पर भी जोर दिया, जो विनिर्माण के साथ-साथ हाइड्रोजन वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से 100 से अधिक उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाकर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास को एक दिशा दी है, जिसके तहत डेढ़ हजार से अधिक लेयर में डेटा को संसाधित करके मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बड़ी शक्ति देकर भविष्य का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थिति:

- ऑटोमोबाइल उद्योग में यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी ऑटोमोबाइल वाहन शामिल हैं।
- भारत का मोटर वाहन बाज़ार वर्ष 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था जो वर्ष 2027 में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता है।

- वर्ष 2025 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाज़ार 50.000 करोड़ (7.09 अमेरिकी डॉलर) तक पहुँचने की उम्मीद है।
- इस उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी 7.1% एवं निर्यात में हिस्सेदारी 4.7% है|

ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिये की गई पहल

- इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत पूर्ण लाइसेंसिंग के साथ 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिये पीएलआई योजना (3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत) उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्यं श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने हेतु 18% तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित करती है।
- ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016-26 भारत में ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के विकास की दिशा को रेखांकित करती है, जिसमें अनुसंधान, डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, निर्माण, आयात/निर्यात, बिक्री को नियंत्रित करने के साथ ही ऑटोमोटिव वाहनों, घटकों और सेवाओं का उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण शामिल है।
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (NEMMP) भरोसेमंद, किफायती और सक्षम एक्सईवी (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) को प्रोत्साहित करने के लिये शुरु की गई है जो सरकार-उद्योग दोनों के सहयोग से उपभोक्ताओं के प्रदर्शन और कीमत संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर सके।

भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में नई दिल्ली में भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पार्नप्री बहिधा नुकारा ने की है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 9वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त, 2022 को बैंकॉक में आयोजित की गई थी।
- इस बैठक में रणनीति, रक्षा, सुरक्षा, कारोबार व निवेश, कनेक्टिविटी समेत नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर कई समझौता हुआ। साथ ही भारत-आसियान और बहुराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग पर भी चर्चा की गई।
- इसके अलावा भारत और थाइलैंड के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्दति में सहयोग को लेकर एक समझौता भी हुआ है। यह समझौता राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और थाईलैंड सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के द्वारा की गई|
- यह पहल आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने और विकसित करने के लिए की गई है।
- यह समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक एवं तकनीकी गतिविधियों के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने, अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान एवं पारंपरिक चिकित्सा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का संचालन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत - थाईलैंड संबंध का अवलोकन

- थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1947 से ही स्थापित है। ये संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर निर्मित हैं|
- भारत और थाईलैंड दोनों दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार हैं। वे आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) समूहों में निकटता से सहयोग करते हैं।
- भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- दोनों देशों के रक्षा सहयोग के तहत रक्षा संवाद बैठकें, सेनाओं के बीच आदान-प्रदान, उच्च-स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। इस अभ्यास में थल

सेना द्वारा अभ्यास मैत्री, वायु सेना द्वारा सियाम भारत अभ्यास एवं नौसेना द्वारा भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती शामिल है|

- भारत और थाईलैंड बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) ढाँचे के लिये बंगाल की खाड़ी पहल के तहत भी क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिये मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से भूमि संपर्क का विस्तार होने की उम्मीद है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन गया है।
- भारत और थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलों, त्योहारों और कार्यक्रमों के लिये नियमित यात्राओं के साथ एक मज़बूत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है। दोनों देश बौद्ध धर्म के द्वारा आपस में एक-दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं | इसके अलावा एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे अब स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के रूप में जाना जाता है, बैंकॉक में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था।

WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने और डब्ल्यूटीओ के भविष्य के काम पर कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर के मंत्री भाग लेंगे।
- सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री एच.ई. डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी द्वारा की जा रही है।
- डब्ल्यूटीओ इस सम्मेलन में विशेष रूप से मत्स्य पालन, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में प्रगति की उम्मीद की जा रही है। लेकिन बड़े सौदे होने की संभावना नहीं है क्योंकि इसके लिए सभी 164 सदस्य देशों के बीच पूर्ण सहमति की आवश्यकता होगी।
- ध्यान रहे, जून 2022 में जिनेवा मुख्यालय में आयोजित डब्ल्यूटीओ की आखिरी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, व्यापार मंत्रियों ने समुद्री जीवन के लिए हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक समझौता किया और COVID-19 टीकों के लिए अस्थायी पेटेंट छूट पर सहमति भी व्यक्त की थी।
- उन्होंने विवाद निपटान प्रणाली को फिर से स्थापित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया, जिसे वर्ष 2019 में वाशिंगटन ने डब्ल्यूटीओ की अपील अदालत में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को वर्षों तक रोक दिया था।
- हालांकि कृषि जैसे प्रमुख मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ में प्रगति पर संदेह है, अन्य मोर्चों पर छोटी प्रगति की उम्मीद है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए सहायता।
- इस सम्मेलन में दो नए देशों, कोमोरोस और पूर्वी तिमोर को डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के रूप में स्वीकार किए जाने की उम्मीद है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर चीन और

यूरोपीय संघ सहित 120 से अधिक देशों ने 26 फरवरी की शुरुआत में एक मंत्रिस्तरीय घोषणा जारी की, जो विकास में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक समझौते को अंतिम रूप देने का प्रतीक है।

- उन्होंने डब्ल्यूटीओ में सौदे के आधिकारिक एकीकरण का अनुरोध करते हुए एक सबमिशन भी जारी किया, लेकिन कुछ राजनयिकों को भारत के विरोध का डर है, जो ऐसे किसी भी समझौते को खारिज कर देता है जिसमें सभी सदस्य देश शामिल नहीं होते हैं।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है।
- यह 1 जनवरी, 1995 को अस्तित्व में आया | वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
- WTO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश शामिल हैं, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा रखते हैं। साथ ही ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।
- WTO की संरचना में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका गठन WTO के सभी सदस्यों देशों से मिलकर होता है, इसके सभी सदस्यों को कम-से-कम हर दो वर्ष में मिलना आवश्यक है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

WTO का कार्य:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना।
- व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिये बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करना।
- व्यापार विवादों का समाधान करना।
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना।
- वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना।

विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना।

भारत के पहले स्टार्टअप महाकुंभ

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कार्यक्रम से पहले, स्टार्टअप महाकुंभ की आयोजन समिति 27 फरवरी 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करने के लिए उपस्थित हुए।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप महाकुंभ, एक अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम है जो ASSOCHAM, NASSCOM, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन, TiE और इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) द्वारा आयोजित किया जा रहा है|
- यह कार्यक्रम उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत

व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) और ज़ोमैटो द्वारा समर्थित है।

- स्टार्टअप महाकुंभ की थीम 'भारत इनोवेट्स' है जो नवाचार और स्टार्टअप के बीच जटिल संबंध को दिखाती है। यह आयोजन इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा और देश के वैश्विक स्टार्टअप फुटप्रिंट को बढ़ाएगा।
- यह आयोजन परिमाण, पैमाने और प्रभाव के मामले में अपनी तरह का पहला आयोजन होने की उम्मीद है, और इसे 18-20 मार्च, 2024 तक प्रतिष्ठित भारत मंडपम और प्रगति मैदान में आयोजित किया जाना है।
- स्टार्टअप महाकुंभ का लक्ष्य स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, सूनीकॉर्न, निवेशकों, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र

हितधारकों का सबसे बड़ा मिलन समारोह बनना है। यहाँ उद्यमिता, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत की कहानी प्रदर्शित करने के लिए सभी एक छत के नीचे उपस्थित होंगे।

मेगा स्टार्टअप इवेंट विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा जो भारत में एक मजबूत और लचीला स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देगा। यह उद्देश्य परामर्श सत्र, मास्टरक्लास, मुख्य भाषण और यूनिकॉर्न गोलमेज सम्मेलन सहित कई गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

- इस कार्यक्रम में वीसी, एंजेल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज और एचएनआई जैसे आविष्कारकों के साथ-साथ संभावित कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ स्टार्टअप को जोड़ने के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप, 10 से ज्यादा थीमेटिक ट्रैक्स, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 500 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधियों, 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमियों और तीन दिनों की अवधि में 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक विजिटर्स की मेजबानी की उम्मीद है।

पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में प्रदान किए जाने वाले पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि पेय जल सर्वेक्षण ने स्रोत और नागरिक स्तर पर स्वतंत्र एनएबीएल प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से स्वच्छ पानी सुनिश्चित किया। जीआईएस-सक्षम वेब पोर्टल, जियो-टैगिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग का उपयोग करके, सर्वेक्षण ने सटीक और पारदर्शी डेटा एकत्र किया।
- 5 लाख घरेलू प्रतिक्रियाओं और एक हजार से अधिक जगहों में अपने सर्वेक्षण के साथ, इसने एक व्यापक आंकलन को प्राथमिकता दी, जिसमें 24,000 से अधिक जल के नमूनों का परीक्षण भी शामिल है।
- पेयजल सर्वेक्षण के परिणामों से यूएलबी निर्णय लेने, सेवा वितरण को बेहतर बनाने और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने, जल संरक्षण और इसके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में स्वामित्व और ज्ञान प्रसार की भावना पैदा करने की उम्मीद है।
- 1,500 से अधिक पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार यह भव्य कार्यक्रम न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाएगा, बल्कि यह अमृत मित्र पहल के शुभारंभ का भी प्रतीक होगा, जिसमें पूरे देश से विभिन्न स्थानों से महिला एसएचजी लाइव जुड़ेंगी।
- गौरतलब है कि 7 से 9 नवंबर 2023 तक अमृत 2.0 के अंतर्गत चलाए गए "महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए" अभियान से जन्मे, अमृत मित्र का लक्ष्य शहरी जल क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों

(एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल करना है और जिसमें महिलाओं को प्रमुख योगदानकर्ता और घरेलू जल प्रबंधन में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए नामित किया गया है।

- अमृत मित्र का व्यापक लक्ष्य महिलाओं के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करना, पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना, घरों के लिए सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना और लैंगिक असमानता को संबोधित करना है।

स्वयं प्लस प्लेटफार्म

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि SWAYAM, बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाला एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म है | इसे वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- एनईपी 2020 के अनुरूप, SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म में अब उद्योग की जरूरतों का समर्थन करने वाले पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं।
- L&T, Microsoft, CISCO और अन्य उद्योग दिग्गजों के सहयोग से विकसित, SWAYAM प्लस में बहुभाषी सामग्री, AI-सक्षम मार्गदर्शन, क्रेडिट पहचान और रोजगार के रास्ते जैसे नवीन तत्व शामिल हैं।
- SWAYAM प्लस समय के साथ मूल्य वर्धित सेवाओं के रूप में मेंटरशिप, छात्रवृत्ति और नौकरी प्लेसमेंट तक पहुंच जैसी सुविधाओं को लाने की भी कल्पना करता है | इस प्रकार यह शिक्षार्थियों के लिए सभी स्तरों पर प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के साथ अपस्किलिंग/री-स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है।

- स्वयं प्लस मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल करने पर केंद्रित है :
- शिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम प्रदाताओं, उद्योग, शिक्षाविदों और रणनीतिक भागीदारों सहित पेशेवर और कैरियर विकास में सभी हितधारकों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण;
- एक ऐसे तंत्र को सक्षम करना जो सर्वोत्तम उद्योग और अकादमिक भागीदारों द्वारा पेश किए गए उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणपत्रों और पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट मान्यता प्रदान करता है ;
- देश भर में शिक्षा प्रदान करके एक बड़े शिक्षार्थी आधार तक पहुँचना, जिसमें टियर 2 और 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षार्थियों तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और स्थानीय भाषाओं में संसाधनों के माध्यम से सीखने के विकल्पों के साथ चुने हुए विषयों में शिक्षार्थी की जरूरतों के आधार पर रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रमों की पेशकश करना।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत में हर साल 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day)' मनाया जाता है।
- गौरतलब है कि 28 फरवरी, 1928 को भौतिक विज्ञानी सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसे चिह्नित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनता को विज्ञान के महत्त्व और इसके अनुप्रयोग का सन्देश फैलाना है।
- केंद्र सरकार द्वारा इस दिवस की स्थापना वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की माँग के आधार पर की गई थी।

'रमन प्रभाव' क्या है ?

- प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना में बताया गया कि पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणों का कुछ हिस्सा बिखर जाता है। इस घटना को 'रमन स्कैटरिंग' कहा गया और प्रकीर्णन के कारण को 'रमन प्रभाव'।
- इस खोज में पाया गया कि इन बिखरी हुई किरणों की तरंगदैर्घ्य (wavelength) प्रकाश की किरणों (incident rays) से भिन्न होती है।
- सी.वी. रमन को इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।